Decentralisation of Recruitment of C and D Group Posts

2554. SHRI GOVINDRAM MIRI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that direct recruitment to C and D group posts is decentralised/is done on zonal/regional/divisional basis;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the justification therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (BANKING, REVENUE AND INSURANCE): (SHRI KADAMBUR M.R. JANARTHANAN): (a) to (c) In terms of extant orders, direct recruitment to group 'C' and 'D' posts is required to be made on All-India basis through open advertisment in the Employment News including where it is through Employment Exchange. The procedure is based on the ruling of the Hon'ble Supreme Court in the matter of Excise Superintendent, Malkapatnam, Krishna District, Andhra Pradesh V/S K.B.N. Visweshwara Rao and others (1996 (6) SCALE 676).

Reply to letters of MPs by Ministers

2555. SHRI K. RAHMAN KHAN: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) how many complaints have been received by the Prime Minister from Members of Parliament against the Ministers for not replying to their letters;

(b) what action the Prime Minister's Office has taken on such serious complaints;

(c) what is the remedy for a Member if any Minister deliberately avoids to reply the letters of the M.Ps; and

(d) whether the action of the Ministers not to reply the letters of the MPs be taken as breach of privilege?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (BANKING, REVENUE AND INSURANCE) (SHRI KADAMBUR M.R. JANARTHANAN):

(a) and (b) The Prime Minister's Office received eight complaints from the Members of Parliament agaisnt the Ministers for not replying to the letters of the Members of Parliament during the period April, 1998 to February, 1999. The Prime Minister has replied to all the concerned Members of Parliament and copies of the letters have been endorsed to the concerned Ministeries/Departments for necessary action. Following up the concern and desire of the Prime Minister, the Cabinet Secretary has urged all Secretaries to the Government of India to personally review the situation and to take effective steps to ensure that unacceptable delays do not occur in the disposal of references received from the Members of Parliament, and emphasizing the need to respond to the Honourable Members of Parliament promptly with courtesy and consideration.

(c) and (d) Clear guidelines for dealing with letters received from the Members of Parliament are contained in the Central Secretariat Manual of Office Procedure. These include instructions to the effect that communications received from the Members of Parliament should beattended to promptly. Each communication is to be replied to within 15 days; where a delay is anticipated in sending a final reply, or where information is to be collected from offices other than the Ministry to which letter pertains, an interim reply should be sent within a fortnight indicating the possible date by which a final reply can be given. Disposal of references from the Members of Parliament should be personally monitored by the senior officer periodically. Any violation of the procedure is dealt with as per the conduct rules.

As the letters sent by the Members of Parliament pertain to a large variety of issues which are dealt with by various organisations, including public sector undertakings, attached and subordinate offices, State Governments etc., the Ministries/Departments concerned have to collect the relevant material from the agencies concerned and to prepare the appropriate replies which, at times, take considerable time. Therefore, it does not seem possible to fix any time schedule during which all matters raised in the letters of the Members

of Parliament could be finalised and final reply could be sent to them. For the same reason, it may not be appropriate to treat this time taken by the Ministers to send reply as an indication of breach of privilege.

प्रधान मंत्री कार्यालय में स्थापित भ्रष्टाचार रोध सेल

2556. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संयुक्त मोर्चा के शासन काल में प्रधान मंत्री कार्यालय में स्थापित भ्रष्टाचार रोधी सेल की स्थापना कब की गई थी;

(ख) इस सेल की स्थापना के उद्देश्य क्या थे;

(ग) 28.02.1999 तक इस सेल में भ्रष्टाचार के कितने प्रकरण विभाग-वार प्राप्त हुए; और

(घ) उन पर की गई कार्रवाई एवं सेल की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त (बैंकिंग, राजस्व और बीमा) मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन): (क) इस बारे में पूर्व प्रधान मंत्री द्वारा घोषणा किए जाने के तत्काल पश्चात् ही, प्रधान मंत्री के कार्यालय में दिनांक 17.08.1997 को भ्रष्टाचार निरोधी एकक को स्थापित कर दिया गया था।

(ख) इस एकक का उद्देश्य, भ्रष्टाचार-निरोध संबंधी शिकायतों और मामलों को प्रभावी ढंग से लगातार आगे बढ़ाते रहना और उन पर नज़र रखे रहना है।

(ग) और (घ) शिकायतों संबंधी ब्यौरा अनुपत्र में दिया गया है। देखिए परिशिष्ट 186, अनुपत्र संख्या 46,

सभी शिकायतें प्रत्येक संबंधित मंत्रालय/विभाग में संयुक्त सचिव के स्तर के पदनामित नोडल अधिकारियों को भेज दी जाती हैं। उपर्युक्त नोडल अधिकारी, एकक द्वारा उन्हें भेजी गई भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों के समन्वयन के उत्तरदायी होते हैं। संबंधित मंत्रालय/विभाग, भ्रष्टाचार के सभी मामलों की यथा आवश्यक समय-बद्ध जांच-पड़ताल और उनका अन्वेषण करवाने के उत्तरदायी, अपने सचिव द्वारा अनुमोदित प्रतिपुष्टि-परक (फीड बैक) रिपोर्टें पाक्षिक रूप से (हर पखवाड़े में) प्रधान मंत्री के कार्यालय को प्रस्तुत करते हैं।

प्रधान मंत्री कार्यालय को प्राप्त हुई शिकायतें

2557. **श्री ईश दत्त यादव:**

चौधरी हरमोहन सिंह यादव:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधान मंत्री कार्यालय द्वारा प्रतिमाह औसतन कितनी लोक शिकायतें प्राप्त की जाती हैं;

(ख) कितनी शिकायतों का निवारण किया गया और कितनी शिकायतें लंबित पड़ी हैं;

(ग) यह शिकायतें किस प्रकार की हैं;

(घ) क्या सरकार का ब्लाक-स्तर पर सार्वजनिक शिकायतें निवारण मशीनरी स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त (बैंकिंग, राजस्व और बीमा) मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन): (क) प्रधान मंत्री कार्यालय में दिनांक 1.4.98 से 28.2.99 के दौरान प्रत्येक माह प्राप्त हुई लोक शिकायतों की औसत संख्या 10,833 थी।

(ख) प्राप्त हुई सभी शिकायतों की, बिना अपवाद के, छान-बीन की जाती है और इन्हें समुचित कार्रवाई के लिये संबंधित प्राधिकारियों को भेज दिया जाता है।

(ग) लोक शिकायतों का संबंध मुख्यत: बेरोजगारी, अपर्याप्त एवं घटिया नागरिक सुविधाओं, वित्तीय सहायता, कानून और व्यवस्था आदि से होता है।

(घ) और (ङ) राज्य, जिला और ब्लाक स्तर पर प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाई और उनका निवारण मुख्यत: राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। राज्य सरकारों को यह सुझाव देते हुए पत्र लिखे गए हैं कि वे राज्य, जिला, ब्लाक और तालुका के सभी स्तरों पर उपयुक्त लोक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करें। अलग-अलग राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रकार के शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किए गए हैं।

Foreign Training of Government Officials

2558. SHRI GANDHI AZAD: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether applications received in response to Department of Personnel and Training letter dated 26th February, 1998 regarding foreign training have been processed;